वर्षः 14 - अंक : 151, मुंबई, शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®

अब हर सच होगा उजागर

DESI VILLAGE
RESTAURANT & CAFE
DUBAI

सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों की खैर नहीं

सीएम एकनाथ शिंदे बोले- दर्ज कराए एफआईआर

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। ठाणे से नासिक, ठाणे से अहमदाबाद हाईवे पर गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कड़ी नाराजगी जताई है। ट्रैफिक जाम से होने वाली समस्याओं से नागरिकों को तत्काल राहत दिलाने के लिए विभाग को दिन-रात एक कर गड्ढों को भरना चाहिए। इसके लिए आधुनिक तकनीक से गड्ढे भरते समय रैपिड क्विक सेटिंग हार्डनर, एम सिक्सटी का प्रयोग कर गड्ढों को भरा जाए। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और नागरिकों को राहत मिलेगी। जहां गड्ढों को भरने के लिए समय की आवश्यकता हो वहां प्रीकास्ट पैनल का उपयोग किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि वे शुक्रवार यानी आज हाई-वे पर मरम्मत कार्य का निरीक्षण करेंगे। (शेष पृष्ठ 3 पर)

कोर्ट ने स्वीकारी नवलानी के खिलाफ एसीबी की 'क्लोजर रिपोर्ट'

संजय राउत ने लगाए थे करप्शन के आरोप

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने कारोबारी जितेंद्र नवलानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर, विभिन्न कंपनियों से 58.96 करोड़ रुपये से अधिक कथित रूप से स्वीकार करने के मामले में एसीबी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। महाराष्ट्र पुलिस के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने अप्रैल 2022 में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की शिकायत पर नवलानी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। राज्यसभा सदस्य राउत ने ईडी अधिकारियों पर नवलानी की मदद से जबरन वसूली का रैकेट संचालित करने का आरोप लगाया था। विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश ए ए नंदगांवकर ने बुधवार को एसीबी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। (शेष पृष्ठ 3 पर)

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर लगेगा ब्रेक

वैनगंगा-नलगंगा प्रोजेक्ट पर कैबिनेट की मुहर

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। कभी बेमोसम की मार तो कभी सूखे की समस्या के कारण फसलों की बबार्दी, महाराष्ट्र के अन्नदाता किसानों पर हर साल कहर बनकर टूटती है। इस वजह से राज्य में हजारों किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों की आत्महत्या रोकने की दिशा में महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने बड़ा कदम उठाया। किसान आत्महत्या से प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे चार लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। (शेष पृष्ठ 3 पर)

एसआरए ने एक साल में बिल्डरों से वसूलें 700 करोड़

नियुक्त किये गए थे 25 नोडल अफसर

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), झोपड़पट्टियों में रहने वालों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काम करता है। एसआरए योजना के तहत जब झोपड़पट्टी की जगह बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, उस वक्त योजना में पात्र झोपड़ी धारकों को किराया देना अनिवार्य होता है। लेकिन कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि बिल्डरस शुरूआत में किराया देते है, लेकिन कुछ समय बाद किराया देना बंद कर देते है। इसलिए प्राधिकरण ने किराया वसूली को लेकर अभियान शुरू किया था, जिसके तहत 25 नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए थे। (शेष पृष्ठ 3 पर)

किराया नहीं मिलने पर की जा सकती है ऑनलाइन शिकायत

एसआरए ने झोपड़ीधारकों को किराया नहीं मिलने पर शिकायत करने का ऑनलाइन विकल्प दिया है। कुछ दिनों पहले ही इसकी शुरूआत की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, योजना में बकाया किराये की समीक्षा के लिए प्राधिकरण ने सरकार की सूची में प्रमाणित लेखा परीक्षकों को अधिकृत किया है और उनके माध्यम से संगठन में जाकर बकाया किराये की समीक्षा की जा रही है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

भारत का दुर्भाग्य

ओलिंपिक जैसे सर्वोच्च खेल मंच पर एक भारतीय की कामयाबी-नाकामी पर परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं हों, तो उससे भारत के बारे में क्या समझ बननी चाहिए? हम किस मुकाम पर आ गए हैं, जहां कुछ भी तुच्छ सियासत से ऊपर नहीं है?

विनेश फोगट को जिन हालात में कुश्ती से संन्यास लेना पड़ा, बेशक यह उनके साथ-साथ इस देश की भी बदकिश्मती है। किंतु एक एथलीट की सफलता और विफलता पर यह देश जिस तरह बंटा नजर आया, उसे भारत का और भी बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा। मंगलवार को विनेश ने जब असाधारण प्रदर्शन करते हुए कुछ घंटों के अंतराल पर तीन प्रतिद्वंद्वियों को धराशायी कर दिया, तो अपेक्षित यह था कि उस पर सारा देश एक स्वर में जश्न मनाता। आखिरकार उन कामयाबियों के साथ ओलिंपिक पदकों की खातिर तरसते भारत के लिए कम-से-कम एक रजत तय हो गया था। मगर हुआ यह कि विनेश की सफलता विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधने का औजार बन गई। विपक्षी और सिविल सोसायटी के एक बड़े हलके में इसे मोदी सरकार की हार के रूप पेश किया गया। स्पष्टतः संदर्भ पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों का था, जिसमें विनेश सहित कई महिला पहलवानों ने कुश्ती परिसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उसके बावजूद सत्ताधारी दल बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा रहा। बहरहाल, अगली सुबह तक सारा नजारा बदल गया। देश को एंटी-क्लाइमेक्स के रू-ब-रू होना पड़ा। तो अब सोशल मीडिया पर जश्न मनाने का की बारी भाजपा समर्थक ट्रोल्स की थी। लेकिन ओलिंपिक जैसे सर्वोच्च खेल मंच पर एक भारतीय की कामयाबी और नाकामी पर ऐसी परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं हों, तो उससे इस देश के बारे में क्या समझ बननी चाहिए? हम किस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं, जहां कुछ भी तुच्छ सियासत से ऊपर नहीं है? यह गहरे आत्म-मंथन का विषय है कि ऐसी मानसिकताओं के बारे में इस देश और इसकी अगली पीढ़ियों का क्या भविष्य होगा? कला और साहित्य के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों के प्रति ऐसा तीखा बंटवारा पहले ही हो चुका है। बहरहाल, उन क्षेत्रों में राजनीतिक विचारधारा एक महत्त्वपूर्ण तत्व होती है, इसलिए उसका एक संदर्भ हो सकता है। मगर खेल में तो अब तक यही माना जाता था कि खिलाड़ी सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विनेश फोगट के मामले ने यह भ्रम भी तोड़ दिया है।

आई एम सी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां, आज और कल मुंबई में रहेंगे

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। इत्तेहाद ए मिल्लत कॉन्सिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीरा ए आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान,दो दिवसीय मुंबई में मुस्लिम मशायल हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे आज दोपहर को बरेली शरीफ से चलकर वाई एयर शाम पांच बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहां से होटल सहारा पहुंचेंगे और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे होटल सहारा में ही रात्रि विश्राम करेंगे 10 अगस्त को दोपहर 2 बजे आई एम सी के संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी के गोवंडी शिवाजी नगर लोटस कालोनी

स्थित आवास पर लंच के लिए पहुंचेंगे लंच के बाद लोगों से मुलाकात करेंगे, शाम 6 बजे विर्ले पार्ले स्थित होटल सहारा में मुस्लिम वेलफेयर असोसिएशन द्वारा मुस्लिम माशायल पर हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे रात्रि 9 मौलाना तौकीर रजा खान होटल सहारा में प्रेस को सम्बोधित करेंगे, अगले दिन 11 अगस्त को मुंबई के गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे रात्रि 8 बजे दरगाह मखदूम शाह माहिम पहुंच कर चादर पोशी करेंगे और दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी जी से मुलाकात करेंगे, इस दौरान आई एम सी के संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी मौलाना तौकीर रजा खान सहाब के साथ रहेंगे।

नजूल विधेयक पर बवाल क्यों?

देखा जाए तो इस अधिनियम के विरुद्ध में हो रहे विवाद में भाजपा और विपक्षी नेताओं द्वारा सही एतराज उठाया जा रहा है। यदि सरकार को ऐसा अधिनियम लाना ही था तो उसे नजूल भूमि पर सदियों से बसे हुए परिवारों को पुनर्वास करने की योजना भी बनानी चाहिए थी। यदि नजूल भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त ही कराना है तो इसके हर पहलू पर गहन विचार के बाद ही इसे पेश किया जाना चाहिए था।

बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान सभा में नजूल संपत्ति अधिनियम पेश किया गया। इस बिल को विधान सभा में तो पास कर दिया गया परंतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इसका भारी विरोध हुआ जिसके चलते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की मांग पर इसे सदन ने पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजने का फैसला लेकर इसे फि लहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया।

उत्तर प्रदेश में कड़े और विवादास्पद फैसले लेने के लिए प्रसिद्ध मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया यह फैसला सही जरूर प्रतीत होता है। परंतु जिस तरह इस विधेयक का विरोध उन्हीं की पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में शायद कुछ संशोधन के साथ इसे पुनः पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिस भी जमीन का कोई वारिस न हो और वो सरकार के अधीन हो, उसे नजूल जमीन कहते हैं। गौरतलब है कि औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़ी मात्रा में जमीनों पर कब्जा किया गया था। लेकिन आजादी के बाद जिस भी नागरिक के पास उसकी जमीन के दस्तावेज थे उन्हें उनकी जमीन वापिस मिल गई। परंतु ऐसी कई जमीनें थीं जिनकी मिलकियत के प्रमाण या जीवित स्वामी उपलब्ध नहीं थे। ऐसी जमीनों को सरकार ने अपने पास रखा, जिसे नजूल जमीन कहा गया। आजादी के बाद इस नजूल जमीन पर यदि कोई रह रहा था तो उससे सरकार ने किराया वसूलना शुरू किया और उस जमीन को लंबे समय के लिए लीज पर देना शुरू कर दिया। इसके बावजूद ऐसी कई नजूल जमीनें हैं जिन पर लोग अवैध कब्जा कर रह रहे हैं। कुछ लोग तो निचले स्तर के अधिकारियों से साँठ-गाँठ कर नजूल जमीन के पट्टे भी अपने नाम करवा लेते थे। ऐसी कई जमीनों पर खेती, मंदिर, दुकानें या अन्य प्रतिष्ठान भी बनने लगे।

परंतु जैसे ही उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति अधिनियम पेश हुआ, तो सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जिस-जिस नजूल जमीन पर लोग गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं या जिन नजूल जमीनों की लीज का किराया सरकार को नहीं दिया जा रहा, उस नजूल जमीन को उत्तर प्रदेश की सरकार वापिस ले लेगी और इस भूमि को सरकारी विकास कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। योगी जी द्वारा उठाया गया ये कदम सही था। परंतु विपक्ष को इस बात पर शक है कि विकास कार्य के नाम पर कहीं प्रदेश की लाखों करोड़ की हजारों एकड़ जमीन को अपने खास चुनिंदा लोगों के बीच बाँट दिया जाएगा। इतना ही नहीं भाजपा के विधायक भी इस अधिनियम के विरोध में उतर आये हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में ऐसी कई जमीनें हैं जिन पर शागिर्द-पेशा वाले परिवार रह रहे हैं, जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं परंतु उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। ऐसे में उनका क्या होगा? कई भाजपा विधायकों का तो यह भी कहना है कि एक तरफ तो प्रधान मंत्री आवास योजना से बेघर लोगों को घर दिये जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जो गरीब दशकों से यहाँ रह रहे हैं उन्हें बेघर किया जा रहा है। तो भला ऐसे बिल का क्या औचित्य? जैसे ही इस अधिनियम पर राजनीति तेज हुई विपक्ष भी खुलकर सामने आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध जताते हुए लिखा, नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। भाजपा घर-परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानती है। जब से भाजपा आई है, तब से जनता रोजी-रोटी-रोजगार के लिए भटक रही है, और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास दो जगह का विकल्प है, पर हर एक उनके जैसा नहीं है। बसे बसाये घर उजाड़कर भाजपा वालों को क्या मिलेगा। क्या भू-माफि याओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी?

मालिक,मुद्रक,प्रकाशक-**दिलशाद एस खान** द्वारा एस आर प्रिंटिंग प्रेस,मोहन अर्जुन कंपाउंड, वैशाली नगर दहिसर (पूर्व),मुंबई-68 से मुद्रित व मुंबई हलचल,साईं मंगल को ऑ हॉ सो बी-2-301,इस्माइल बाग नियर मालाड शॉपिंग सेंटर, एस वी रोड,मालाड (प) मुंबई से प्रकाशित RNI NO MAHHIN/2010/34146, फोन:**9619102478 /9821238815**
email: mumbaihalchal@gmail com संपादक: **दिलशाद एस खान,** समाचार पत्र में छपे किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

सड़क पर मां के साथ जा रही थी, पांचवीं मंजिल से गिरा पालतू कुत्ता, बच्ची की मौत

मुंबई हलचल/संवाददाता

ठाणे। मुंब्रा में अपनी बिल्डिंग के पास सड़क पर अपनी मां के साथ चल रही चार साल की बच्ची की पांचवीं मंजिल की छत से पालतू लैब्राडोर के गिरने से मौत हो गई। यह दुखद घटना दरगाह रोड पर चिराग मेंशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि, मुंब्रा पुलिस ने बताया कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि कुत्ता सड़क पर कैसे गिरा - क्या वह कूदा या फेंका गया। कुत्ते को कई फ्रैक्चर हुए हैं और उसे करनाला के रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी सना खान की मौत में किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है, लेकिन मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल शिंदे ने कहा कि पुलिस ने

जांच शुरू कर दी है। पड़ताल की जा रही है कि कई कुत्तों को पालने वाले शख्स के पास इन्हें पालने का लाइसेंस था या नहीं। रिश्तेदारों ने बताया कि सना एक कैटरर की इकलौती बेटी थी, जिसे गर्भधारण करने में आठ साल लग गए। सना के मामा आसिफ रंगरेज ने बताया कि मंगलवार को शाम करीब साढ़े चार बजे मां-बेटी चिराग मेंशन ए-विंग से बाहर निकलकर पास की दुकान पर डायपर का पैकेट बदलने गई थीं, तभी बी-विंग की छत से कुत्ता उनकी भतीजी पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सना को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया और बाद में सीटी स्कैन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि, वहां पहुंचने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने ईसीजी किया और उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का गहन पंचनामा किया और सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। रंगरेज ने आरोप लगाया कि कुत्ते के मालिक ने पूरी छत पर कब्जा कर लिया है और संभवतः बिना उचित अनुमति के अलग-अलग नस्लों के कुत्ते पाल रखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'यह घटना कुत्ते के मालिक की लापरवाही के कारण हुई। पुलिस को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।' ठाणे नगर निगम की पशु चिकित्सक क्षमा शिरोडकर ने कहा कि वे आरोपों की जांच करेंगे और अगर आरोप सही पाए गए तो उचित कार्रवाई की जाएगी। शिरोडकर ने कहा, 'हम यह भी जांच करेंगे कि पालतू जानवर के मालिक ने जानवरों के साथ कोई क्रूरता की है या नहीं।'

पुणे में जीका वायरस के 8 नए मामलों समेत कुल संक्रमितों की संख्या हुई 81, 32 गर्भवती महिलाएं, महाराष्ट्र अलर्ट

मुंबई हलचल/संवाददाता

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में जीका के आठ नए मामले सामने आए, जिससे जिले में कुल संख्या 81 हो गई। पुणे नगर निगम (पीएमसी) के रिपोर्ट किए गए सात रोगियों में से 6 गर्भवती महिलाएं हैं। वहीं एक 36 वर्षीय पुरुष की हालत खराब है। इसके साथ ही शहर में जीका के मामलों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। ग्रामीण पुणे में छह और पिंपरी चिंचवाड़ शहर में दो मामले सामने आए हैं। बुधवार को जीका पॉजिटिव होने की पुष्टि करने वाली छह गर्भवती महिलाओं में से कम से कम पांच का विसंगति स्कैन सामान्य बताया गया था। ग्रामीण पुणे में, पुरंदर का एक 31 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने हैदराबाद की यात्रा की थी और बुखार और लाल चकत्ते जैसे

लक्षणों की सूचना दी थी। उनकी हालत स्थिर बताई गई है। अब तक जीका वायरस के चार मरीजों की मौत हो चुकी है। खास बात है कि पुणे में सबसे ज्यादा जीका वायरस संक्रमण का पता महिलाओं में चल रहा है। इससे पहले 26 गर्भवती महिलाएं संक्रिमत मिली थीं, अब एक दिन में छह और महिलाओं के संक्रमित होने से जीका वायरस प्रभावित गर्भवती महिलाओं की संख्या 32 हो गई है। अफसरों ने बताया कि सबकी हालत स्थित है। इस साल पुणे में जीका वायरस के संक्रमण का पहला मामला 20 जून को सामने आया था। 46 वर्षीय डॉक्टर का परीक्षण सकारात्मक आया था। बाद में उनकी 15 वर्षीय बेटी भी वायरस से संक्रमित पाई गई थी। पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि देश में किसी भी मौत को सीधे जीका वायरस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। हालांकि, विभाग अभी भी चार मृतक मरीजों की रिपोर्ट समीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार की मृत्यु लेखा परीक्षा समिति को भेजेगा।

गर्भावस्था में जीका वायरस खतरनाक

गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस का संक्रमण माइक्रोसेफली का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें असामान्य मस्तिष्क विकास के कारण बच्चे का सिर काफी छोटा होता है। यह वायरस संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। पीएमसी स्वास्थ्य विभाग मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए निगरानी और धूम्रीकरण सहित प्रकोप को नियंत्रित करने के उपाय कर रहा है।

'बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को फंसा देती हैं, महिला अत्याचार कानून का दुरुपयोग'

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आईपीसी की धारा 498ए (पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी पर क्रूरता) के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में देखा गया है कि बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को भी महिला अत्याचार के मामलों में फंसाया गया है। अब इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 के रूप में शामिल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ससुराल में क्रूरता का शिकार होने वाली पीड़िताओं के

प्रति हमारी हमदर्दी है, लेकिन उक्त धारा के दुरुपयोग की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि क्रूरता से संबंधित इस धारा के तहत बिस्तर में पड़े अपाहिज बुजुर्गों को भी फंसाया जाता है, ऐसे में यदि धारा 498ए से जुड़े अपराध को समझौता योग्य (कंपाउंडेबल) बना दिया जाता तो, इस धारा से जुड़े हजारों मामलों का समाधान हो सकता है। इस पर, केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील डी. पी. सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए थोड़ा समय दिया जाए।

(पृष्ठ 1 का समाचार)

सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों की खैर नहीं

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग, एमएसआरडी, लोक निर्माण, यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों को इस काम को तुरंत पूरा करने और नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि कोंकण विभागीय आयुक्त को पीक आवर्स के दौरान भारी यातायात के नियम और भारी वाहनों के लिए राजमार्ग के किनारे पार्किंग स्थल के लिए एक संयुक्त अधिसूचना जारी करनी चाहिए। वही दूसरी ओर नासिक-भिवंडी रोड का बुरा हाल है। इससे आवागमन में परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम में सड़क की हालत खराब हो गई है। इससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक ओर जहां सड़कों पर गड्ढे भरने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक वार्डन की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया है। इस भारी यातायात को नियंत्रित करने के लिए भारी वाहनों को जेएनपीटी से नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि जेएनपीटी से आने वाले भारी वाहनों से जाम न लगे। इसके समन्वय के लिए कलेक्टर ठाणे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीएम ने आदेश दिया है कि जेएनपीटी से पनवेल, पुणे, ठाणे की ओर जाने वाले राजमार्ग पर गड्ढों को भरा जाए। सिडको को नवी मुंबई, पनवेल, जेएनपीटी क्षेत्र से आने वाले यातायात को विनियमित करने के लिए नवी मुंबई पुलिस को 200 ट्रैफिक वार्डन प्रदान करना चाहिए और जेएनपीटी को भारी वाहनों के लिए आवश्यक क्रेन प्रदान की जाए।

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर लगेगा ब्रेक

वैनगंगा नलगंगा परियोजना के तहत गोदावरी उप-बेसिन से वैनगंगा का पानी बुलढाणा जिले में वैनगंगा परियोजना तक लाया जाएगा। इसके लिए कुल 426।52 किमी लंबी कनेक्टिंग नहरों का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग विदर्भ के नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा जिलों के 15 तालुकाओं में सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 31 भंडारण तालाबों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि रबी सीजन में पानी का उपयोग किया जा सके। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2018 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। केंद्रीय जल आयोग ने भी इसे मंजूरी दे दी है और राज्य जल परिषद की बैठक में इस परियोजना को एकीकृत राज्य जल योजना में शामिल कर लिया गया है। महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा इंटरलिंकिंग परियोजना पर कैबिनेट की मुहर लगने से किसानों की आत्महत्या से प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी कृषिक समृद्ध बनेंगे। 87 हजार 342 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और मराठवाड़ा जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष लाभ होगा।

मुंबई में एसआरए ने एक साल में बिल्डरों से वसूलें 700 करोड़

साथ ही एसआरए ने परिपत्र 210 जारी किया था, जिसके तहत डेवलपर को नई परियोजनाएं स्वीकार करते समय 2 साल का अग्रिम किराया चेक (डीडी) और तीसरे वर्ष का पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) जमा करना अनिवार्य कर दिया गया था। यही वजह है कि जुलाई 2023- 24 के बीच इस योजना के तहत 700 करोड़ से अधिक किराया एकत्र किया गया है। उसके माध्यम से झुग्गीवासियों को प्राधिकरण के माध्यम से किराये का वितरण किया जा रहा है। साथ ही किराया नहीं देने वाले डेवलपर के खिलाफ भी प्राधिकरण धारा 13(2) के तहत डेवलपर को हटाने की कार्रवाई कर रहा है।

कोर्ट ने स्वीकारी नवलानी के खिलाफ एसीबी की 'क्लोजर रिपोर्ट'

सी-समरी रिपोर्ट तब दाखिल की जाती है जब पुलिस जांच में यह निष्कर्ष निकालती है कि गलत तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायत के अनुसार, नवलानी ने वित्तीय वर्ष 2015 से 2021 के दौरान अपने व्यक्तिगत और कंपनी बैंक खातों में 39 निजी कंपनियों के माध्यम से कुल 58.96 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। एसीबी ने कहा कि जांच से पता चला कि ये लेन-देन इन 39 निजी कंपनियों और नवलानी के बीच नियमित व्यापारिक लेनदेन से संबंधित थे। इसलिए, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि नवलानी ने इन धनराशियों को अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए अपने पद या प्रभाव का दुरुपयोग किया है। एसीबी की रिपोर्ट में कहा गया कि राउत ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि वह कथित कदाचार में किसी भी ईडी अधिकारी की संलिप्तता से अनभिज्ञ थे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने एसीबी को दिए गए बयान में कहा कि 39 कंपनियों में से किसी ने भी वास्तव में कारोबारी के आचरण के बारे में उससे शिकायत नहीं की थी। राउत ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या नवलानी ने निजी कंपनियों से धन प्राप्त करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ईडी या उसके अधिकारियों का 39 कंपनियों द्वारा नवलानी को भुगतान की गई कुल 58.96 करोड़ रुपये की राशि से कोई संबंध नहीं था।

वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर सत्तापक्ष और विपक्ष में रार-पलटवार, सदन में अखिलेश पर भड़के शाह

जिलाधिकारी को ज्यादा अधिकार देने पर अखिलेश ने जताई नाराजगी

आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं, न ही कोई न्यायाधीश, गोलमोल बातें करना बंद कीजिए

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हो गया है। इसके साथ ही जैसी कि अनुमान था कि इस पर आरोप-प्रत्यारोप और राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने विधेयक का लोकसभा में ही विरोध शुरू कर दिया। विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान के मूल पर हमला बताया है।

संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में 'वक्फ संशोधन विधेयक-2024' पेश किया। इस दौरान सदन में विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में इस बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया। सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान शाह सपा मुखिया पर भड़क गए।

अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक बहुत सोची-समझी राजनीति के तहत किया जा रहा है। उन्होंने अगर आप एक जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को सामना करना पड़ा। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है।

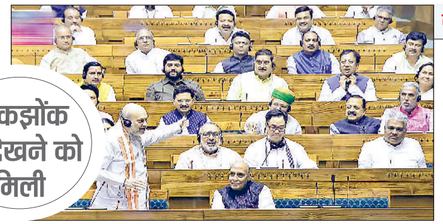

नोकझोंक भी देखने को मिली

अध्यक्ष के अधिकार हम सब के लिए

अखिलेश के इस जवाब पर शाह ने भड़कते हुए कहा कि अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ अखिलेश विपक्ष का नहीं, हम सब का है। आप इस तरह की गोलमोल बातें नहीं कर सकते हैं। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी में भी सियासत तेज हो गई है।

विपक्ष ने किया हंगामा

विधेयक का विरोध करूंगा: अखिलेश

सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो पेश किया गया है, वह बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। मैंने सुना है कि आपके भी कुछ अधिकारों को वापस लिया जा रहा है और हम आपके लिए भी लड़ेंगे। मैं विधेयक का विरोध करता हूं। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री ने आपत्ति भी जताई और कहा कि आप लोकसभा स्पीकर के अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं।

मायावती ने दी प्रतिक्रिया

राष्ट्रधर्म का पालन करे सरकार, दखल न दे

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्रधर्म निभाए। मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म व सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय।

ललन सिंह ने कहा- यह मुस्लिमों के खिलाफ नहीं

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ कैसे है? यह विधेयक सिर्फ पारदर्शिता के लिए लाया गया है। विपक्ष इसकी तुलना मंदिरों से करके मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। केसी वेणुगोपाल को ये बताना चाहिए कि जब हजारों सिखों को मारा गया। किस टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी की हत्या की? अब ये अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन एक कानून द्वारा किया गया। अगर कानून के द्वारा बनाया गया कोई संस्थान तानाशाह हो जाता है तो यह सरकार का अधिकार है कि वह कानून बनाकर पारदर्शिता कायम करे। उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाने का आरोप लगाया।

आरएसपी के रामचंद्रन बोले

वक्फ बोर्ड और परिषद होगी कमजोर

आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद को पूरी तरह से कमजोर कर रही है। आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। यह संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं सरकार को आगाह करता हूं कि अगर इस विधेयक की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की गई तो यकीनी तौर पर यह विधेयक अटक जाएगा।

ओवैसी ने लगाया आरोप

आप मुस्लिमों के दुश्मन हैं

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ विधेयक को लेकर कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना है। यह विधेयक लाकर सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुस्लिमों के दुश्मन हैं।

डीएमके की कनिमोझी बोलीं

यह संविधान का उल्लंघन

डीएमके सांसद कनिमोझी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो कि अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक संस्थों का प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह विधेयक एक धर्म विशेष को निशाना बनाता है।

भारत सरकार का बड़ा फैसला

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सभी वीजा केंद्र अनिश्चितकाल तक किए बंद

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

भारत सरकार ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए एक दिन पहले ही बांग्लादेश स्थित दूतावास और महावाणिज्य दूतावास से अपने अतिरिक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस दिल्ली बुला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद ही सभी वीजा केंद्र बंद रखने का फैसला किया गया है।

बांग्लादेश में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने बांग्लादेश में अपने सभी वीजा केंद्र बंद रखने का फैसला किया है। भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किए गए बयान के अनुसार, 'सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। बांग्लादेश में जारी अस्थिरता के चलते यह फैसला किया गया है। आवेदन की अगली तारीख की जानकारी जल्द ही मैसेज के जरिए दे दी जाएगी।

कई राजनयिकों को वापस बुलाया

भारत सरकार ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए एक दिन पहले ही बांग्लादेश स्थित दूतावास और महावाणिज्य दूतावास से अपने अतिरिक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस दिल्ली बुला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद ही सभी वीजा केंद्र बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी भी बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त और कई अन्य कर्मचारी मौजूद हैं और दूतावास में सामान्य रूप से काम हो रहा है। बांग्लादेश में भारत के एक उच्चायुक्त और चिटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में महावाणिज्य दूत मौजूद हैं।

आरक्षण के विरोध से भड़की हिंसा

बांग्लादेश में 1971 में देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तय किए आरक्षण के खिलाफ जुलाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। धीरे-धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। ये विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि बीते 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। वहीं बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गुरुवार को अंतरिम सरकार का गठन किया जाना है। इस अंतरिम सरकार की देखरेख में ही अगले कुछ महीनों में चुनाव कराए जाने की बात कही गई है।

भारत में शरण मांगने सीमा पर पहुंचे बांग्लादेशी, बीएसएफ ने लौटाया

किशनगंज। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उपद्रव के बीच बांग्लादेशी नागरिक देश छोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि उनके जानमाल की रक्षा हो सके। इसे लेकर किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र से सटे बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बांग्लादेशी नागरिक पहुंचकर भारत में प्रवेश देने के लिए शरण मांग कर रहे हैं। इस संबंध में बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि नार्थ बंगाल फ्रंटियर के अधीनस्थ दो बीओपी पर घुसपैठ की कोशिश की गई। जहां अधिकारियों और जवानों द्वारा समझा-बुझाकर सभी लोगों को वापस भेज दिया है। भारतीय सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों के पहुंचने की सूचना पर बीएसएफ कमांडेंट अजय शुक्ला और इस्लामपुर एसपी जेबी थामस पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।

बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल की मदद से ग्रामीणों को वापस गांव की ओर भेजा गया। बताया जा रहा है कि सीमा पर पहुंचे बांग्लादेशी नागरिक सीमा से सटे गांव क्षेत्र के थे, जो बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत में शरण लेने के लिए प्रवेश की जुगत में थे।

बांग्लादेश हिंसा में हसीना की पार्टी के 29 नेताओं की मौत

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अवामी लीग और इसकी सहयोगी पार्टियों से जुड़े कम से कम 29 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए। अवामी लीग के 20 नेता भी शामिल हैं। अवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।

बढ़ते तनाव को देखते हुए चौहान ने बांग्लादेश में अशांति और अस्थिरता पर जताई चिंता

नई दिल्ली। शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश में अस्थिरता पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने पहली बार चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश में अशांति, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर चिंताओं को उजागर किया। सीडीएस चौहान ने कहा कि तीन साल से चीन के साथ गतिरोध के बावजूद हमारे पास पूर्व और उत्तर में जीवंत सीमाएं हैं। इसलिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति होना निश्चय ही भारत के लिए भी चिंता का विषय है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान गुरुवार को दिल्ली में सैन्य गोला-बारूद पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद वहां अराजकता का माहौल है, जिसने अब वहां सांप्रदायिक रंग ले लिया है। हिंदुओं के साथ ही वहां दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो अब पूर्वोत्तर की सीमा से भारत में पलायन करने की ताक में हैं लेकिन सीमा सुरक्षा बल उन्हें वापस बांग्लादेश भेजकर घुसपैठ को नाकाम कर रहे हैं। भारतीय सेना और बीएसएफ भारत से लगती बांग्लादेश की करीब 4000 किमी. लंबी सीमा पर हाई अलर्ट पर है।

कांग्रेस की दो और राजद की एक सीट जाएगी भाजपा की झोली में

राज्यसभा में बहुमत से केवल 9 अंक दूर राजग

राज्यसभा की खाली हो रही 12 सीटों में से 11 पर होगी भाजपा की जीत

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा से चुनकर आने के कारण उनके द्वारा खाली की गई राज्यसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से ये सीट भाजपा की झोली में जाएगी, मगर चुनाव से पहले ही हुड्डा ने ओलंपिक पहलवान वीनेश फोगाट को उपचुनाव में पक्ष, विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर नया सियासी दांव चल दिया है।

फोगाट के प्रति देश भर में उठ रहे भावावेश के ज्वार का राजनीतिक लाभ लेने की होड़ हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर चल रही है। यही वजह है कि संसद के अंदर हो या बाहर हर तरह की सियासी घेराबंदी की कोशिशें तेज हो गई हैं। तेलंगाना से टीआरएस के राज्यसभा सांसद के. केशव राव ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इससे खाली हुई सीट पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का चुनकर आना तय माना जा रहा है। सितंबर में राज्यसभा की खाली हो रही 12 सीटों में से 11 सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। इस चुनाव के बाद राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 97 हो जाएगी जब कि कांग्रेसी सांसदों की संख्या 27 हो जाएगी। विपक्ष के नेता के लिए उच्चसदन में कम से कम 25 सांसदों की संख्या चाहिए यानी कांग्रेस के पास विपक्षी दल के नेता का पद बच जाएगा। राजग गठबंधन के पास बहुमत से केवल 9 अंकों की दूरी रहेगी। राजग की झोली में 116 सांसदों की संख्या हो जाएगी जब कि बहुमत के लिए 125 सांसदों की संख्या होनी चाहिए। बिहार से खाली हो रही राजद की मीसा भारती की राज्यसभा सीट पर राजग का कब्जा होगा। एक और राज्यसभा की सीट भाजपा के विवेक ठाकुर के पास थी। विवेक ठाकुर नवादा लोकसभा से चुनकर पहुंचे हैं। सो, बिहार की दो राज्यसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में एक-एक सीट भाजपा, जदयू के बीच बंट सकती है। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारी की घोषणा भाजपा ने गठबंधन उम्मीदवार के रूप में पहले ही कर दी है। कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट से भाजपा के बागी नेता भोजपुरी फिल्म कलाकार पवन के खड़े हो जाने के कारण हार का सामना करना पड़ा था।

राजनाथ और सोनिया से मिलीं मनु भाकर

नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने अपने कोच जसपाल राणा के साथ नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

टॉप-अप कर्ज में नियामकीय प्रावधानों का पालन नहीं

'कर्ज के ऊपर कर्ज' में वृद्धि का रुझान सिर्फ कुछ बैंकों तक सीमित : दास

मुंबई हलचल / मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्ज के ऊपर लिए जाने वाले कर्ज (टॉप-अप) में बढ़ोतरी का 'रुझान' व्यवस्थागत मसला न होकर कुछ बैंकों तक ही सीमित है।

दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद कहा, "टॉप-अप कर्ज में नियामकीय प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के साथ आरबीआई द्विपक्षीय स्तर पर निपटेगा और यह कोई व्यवस्थागत समस्या नहीं है। टॉप-अप कर्ज खुदरा कर्ज के साथ आवास ऋण के ऊपर लिया जाने वाला कर्ज है।

आवास इक्विटी कर्ज में वृद्धि हुई

दास ने इससे पहले दिन में कहा था कि आवास इक्विटी कर्ज या टॉप-अप ऋण में उच्च वृद्धि हुई है, जिसमें ऋणदाता स्वर्ण ऋण और आवास ऋण जैसे अन्य गारंटी वाले कर्ज पर टॉप-अप ऋण की पेशकश कर रहे हैं। दास ने कहा कि ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात, जोखिम भार और निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी से संबंधित नियामकीय निर्देशों का कुछ संस्थाओं द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

धन के अंतिम उपयोग की हो निगरानी

गवर्नर ने कहा, "यह प्रणालीगत समस्या नहीं है। कुछ संस्थाओं में हमने यह समस्या देखी है। हम पर्यवेक्षण स्तर पर द्विपक्षीय रूप से उनसे निपटेंगे, लेकिन कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है।" उन्होंने कहा कि चूंकि आरबीआई ने इस 'प्रवृत्ति' को देखा, इसलिए उसने बैंकों को यह संदेश देकर इस मुद्दे को उठाने के बारे में सोचा कि वे धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करके तथा विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करके इस समस्या का प्रबंधन करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

कर्ज का उपयोग गैर उत्पादक क्षेत्र में

दास ने कहा, "इस तरह की प्रक्रियाओं के कारण कर्ज राशि का उपयोग गैर-उत्पादक क्षेत्रों में या सट्टेबाजी के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए, बैंकों और एनबीएफसी को ऐसी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।"उन्होंने कहा, "बैंकों को ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात, जोखिम भार और टॉप-अप के संबंध में धन के अंतिम उपयोग की निगरानी से संबंधित नियामकीय निर्देशों का पालन करना चाहिए।"

- आरबीआई ऐसे बैंकों से द्विपक्षीय तरीकों से निपटेगा
- इसे आरबीआई कोई व्यवस्थागत समस्या नहीं मानता
- खुदरा कर्ज के साथ आवास ऋण के ऊपर लिया जाने वाला कर्ज है

तीसरे पक्ष की प्रणालियां प्रभावित हुई

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस के संयुक्त उद्यम सी-एज का नाम लिए बिना डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि तीसरे पक्ष की प्रणालियां प्रभावित हुई हैं और चूंकि जोखिम अन्य प्रणालियों तक पहुंचने की संभावना थी, इसलिए सक्रिय उपाय के रूप में उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया।

तरलता संबंधी समस्या आ सकती है

दास ने कहा कि ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर से परिसंपत्ति देयता में असंतुलन या तरलता प्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग प्रणाली को संरचनात्मक तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तराखंड में अधिकारियों ने बिना बात के भर दिया 100 करोड़ का आयकर, हर ओर इसकी चर्चा, वन मंत्री बैठाएंगे जांच

मुंबई हलचल/संवाददाता

देहरादून। वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा 100 करोड़ रुपये के आयकर भरने के मामले की जांच की जाएगी। यह आयकर उत्तर प्रदेश वन निगम से मिलने वाली लगभग 560 करोड़ रुपये की उस रकम के सापेक्ष भरा गया है, जो अभी तक उत्तराखंड वन विकास निगम को प्राप्त भी नहीं हुई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। हाल ही में पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह मामला प्रकाश में आया। यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद वन निगम में परिसंपत्तियों का बंटवारा होना था। तीन वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश वन निगम और उत्तराखंड वन विकास निगम के बीच एक करार हुआ। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये देने थे। यह पैसा राज्य बनने के दौरान उत्तराखंड को मिलना था, इसलिए इस पर ब्याज बढ़ता गया और यह रकम कुल मिलाकर अनुसार 560 करोड़ हो गई। यद्यपि यह धनराशि उत्तराखंड को अभी तक नहीं मिली है। इस बीच आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश वन निगम से 560 करोड़ रुपये के संबंध में आयकर चुकाने को कहा तो उत्तर प्रदेश ने इस रकम को उत्तराखंड का बताया। इस पर आयकर विभाग ने उत्तराखंड वन विकास निगम से इस रकम पर आयकर देने को कहा।

उत्तराखंड के विवि में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, छात्र को पहले पास, फिर किया फेल

मुंबई हलचल/संवाददाता

हल्द्वानी। कुमाऊं विवि ने स्नातक तृतीय वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाकर परिणाम जारी करने का दावा किया है। दोबारा आए रिजल्ट में विवि की लापरवाही उजागर हुई है। बीए तृतीय वर्ष के एक छात्र का परिणाम तीन बार संशोधित किया गया। उसे समाज शास्त्र के द्वितीय पेपर में पहले पास दिखाया गया, अंतिम संशोधन यानी बुधवार को जारी हुए परिणाम में फेल कर दिया गया। एमबीपीजी कालेज में गुरुवार को हुए छात्रों के हंगामे के दौरान विवि की लापरवाही सामने आई है। प्रभावित छात्र राहुल आर्या ने बताया कि 24 जून को बीए तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित हुआ था।

इसमें समाज शास्त्र के पहले पेपर में चार नंबर दिए गए थे, जबकि द्वितीय पेपर में अनुपस्थित दिखाया गया था। उन्होंने परीक्षा दिए जाने का प्रमाण लगाकर विवि को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद 12 जुलाई को परिणाम अपडेट किया गया और दूसरे पेपर में उन्हें 44 अंक दिए गए। वहीं 20 जुलाई को आनलाइन अंकपत्र फिर से संशोधित हुआ और समाज शास्त्र के दूसरे पेपर में 47 अंक कर दिए गए। इसके बाद तीसरी बार बुधवार को रिजल्ट फिर से अपडेट हुआ है। इसमें पहले पेपर में तो चार नंबर ही हैं, लेकिन दूसरे में अंक घटाकर 30 कर दिए गए हैं। ऐसे में वह फेल हो गए हैं। इस स्थिति में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनको असल में कितने अंक प्रदान किए गए। इसे लेकर छात्र ने अब आरटीआइ से उत्तर पुस्तिका मांगी है। साथ ही कालेज प्रशासन को भी चारों अंकपत्र की प्रति भी शिकायती पत्र के साथ दी है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

ओरल कैंसर

कुछ आदतों को करें कंट्रोल

लोगों में तंबाकू के बढ़ते प्रयोग के कारण भी मुंह, सिर और गले के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इसके लक्षणों की पहचान इसके शुरूआती चरण में ही कर ली जाए तो समय रहते बचाव संभव है।

ये हैं ओरल कैंसर के लक्षण

- होंठ, मसूड़े और मुंह के अन्य हिस्सों में जख्म, गांठ या अल्सर होना
- निगलने, चबाने या बोलने में परेशानी महसूस होना
- माउथ सोर्स
- जीभ में दर्द होना
- मुंह से अचानक खून निकलना

ओरल कैंसर के लिए ये होती है खतरे की बात

तंबाकू से तैयार होने वाले कोई भी उत्पाद, अल्कोहल का अत्यधिक प्रयोग, सूर्य की रोशनी के अत्यधिक संपर्क में रहना। ऐसा माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ ओरल कैंसर का खतरा भी बढ़ता जाता है।

इस प्रकार करें बचाव

तंबाकू का सेवन न करें : जो लोग तंबाकू को पीने या खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, वे तुरंत इसे बंद कर दें ताकि जख्म होने के खतरे से बच सकें। यदि किसी ने तंबाकू कभी नहीं लिया है तो उसे ऐसा करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए क्योंकि तंबाकू किसी भी रूप में सेहत के लिए खतरनाक होता है और अधिकांश मामलों में ओरल कैंसर का कारण भी।

अधिक मात्रा में न लें अल्कोहल : जो लोग अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें इसकी मात्रा धीरे-धीरे सीमित कर बंद कर देना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार शराब न पीने वालों की तुलना में शराब पीने वालों में ओरल कैंसर का खतरा छह गुना अधिक होता है।

लंबे समय तक धूप में रहने से बचें: धूप में काफी देर तक रहने वालों को होंठ पर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जब भी घर से बाहर निकलें हमेशा यूवी किरणों को ब्लॉक करने वाले लिप बाम या लिप ग्लॉस का प्रयोग करें।

मुंह की करें सही देखभाल: इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने दांतों को नियमित रूप से साफ करें और फ्लॉसिंग करना न भूलें। मुंह की साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखने पर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, कैंसरकारी सेल्स से लड़ना मुश्किल हो जाता है।

फल और सब्जियां करें भोजन में शामिल: ढेर सारी सब्जियां और फलों को अपने रोजाना के भोजन में शामिल करें। इनमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट ओरल कैंसर के खतरे को कम करने का काम करते हैं।

आंखों को रोशन करता है विटामिन ए

विटामिन ए फैट सॉल्यूबल विटामिन है और 13 आवश्यक विटामिनों में से एक है। आंखों से जुड़ी कई सारी कार्यप्रणालियों के सही संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, जिसमें कलर विजन और लो लाइट विजन शामिल हैं। इम्यूनिटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी यह विटामिन आवश्यक होता है। ऐसे में इसकी कमी से कई सारी शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी पूर्ति इस विटामिन से खाद्य पदार्थों के जरिए की जा सकती है।

डाइट से कर सकते हैं पूर्ति

विटामिन ए डिफिशिएंसी की हल्की समस्या में विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने से मदद मिल सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थों में शामिल हैं :

- गाजर, पालक, शकरकंद, शिमला मिर्च
- राजमा, हरी पत्तेदार सब्जियां
- यदि आपको लगता है कि भोजन द्वारा इसके लक्षणों पर फर्क नहीं पड़ रहा तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें।

ओवरडोज की स्थिति

विटामिन ए की अधिकता होने पर विटामिन सी, ई और के की कमी होने लगती है। अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए होने पर उसके लक्षण 6 घंटे के अंदर ही नजर आने लगते हैं और सप्लीमेंट बंद करने के कुछ हफ्तों के बाद ही ये लक्षण चले जाते है। वयस्कों की तुलना में बच्चे विटामिन ए के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए विटामिन ए के सप्लीमेंट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। विटामिन ए डिफिशिएंसी से कई सारी समस्याएं उभरकर सामने आने लगती हैं और साथ ही इसकी अधिकता भी शरीर में टॉक्सीसिटी पैदा करती है।

ये लक्षण भी हैं

- खाने में स्वाद महसूस न होना
- घाव भरने में समय लगना
- आंखों के कॉर्नर में सफेद धब्बे हो जाना
- आंखों से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे कंजंक्टिवाइटिस
- ड्राय स्किन, सूखे, बेजान बाल
- टूटते नाखून कमजोर इम्यून सिस्टम

विटामिन ए डिफिशिएंसी के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं

रतौंधी : विटामिन ए की कमी के सबसे प्रमुख लक्षण रतौंधी या आंखों की कम रोशनी के रूप में नजर आते हैं। रतौंधी की समस्या में कम रोशनी की स्थिति में व्यक्ति देख नहीं पाता। लेकिन सामान्य रोशनी में चीजों को स्पष्ट देख सकता है।

ड्राय आइज : विटामिन ए डिफिशिएंसी की स्थिति में क्रॉनिक ड्राय आइज की समस्या होती है। इसमें आंसुओं का निर्माण नहीं होता, आंखों में चुभन और खुजली जैसी महसूस होती है। आंखों की पुतलियां भी कड़ी महसूस होती हैं। वैसे यह स्थिति कई अन्य कारणों से भी हो सकती है।

कॉर्निया डिसऑर्डर और ब्लाइंडनेस : विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण कॉर्निया का रंग सफेद होने लगता है और अंधेपन की नौबत आ जाती है। ऐसा लंबे समय तक विटामिन ए की कमी के कारण होता है।

खाने में विविधता : विटामिन ए की जरूरत को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है कि विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। इससे पोषण की पूर्ति बड़े पैमाने पर हो पाएगी। नियमित रूप से विभिन्न रंगों वाली सब्जियां और फलों का चुनाव करें, इससे विटामिन का सही संतुलन शरीर में हो पाएगा।

खाना बनाते समय काम आएंगी ये टिप्स

ऐसी कुकिंग टिप्स जो आपके खाना बनाने के दौरान काफी काम आएंगी। जानें ये कुकिंग टिप्स :

- सामान्य मौसम में केलों को बाहर रखने से वे ज्यादा पक जाते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में केलों को फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने से छिलके काले हो जाते हैं, मगर अंदर केला सुरक्षित रहता है।
- टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए उन्हें ब्राउन पेपर बैग में पैक कर किसी डार्क कॉर्नर में रखें। टमाटर जल्दी पक जाएंगे और उनका रंग भी बरकरार रहेगा।
- प्याज को पकाते समय उसमें थोड़ा नमक डाल लें। इससे प्याज जल्द पकेंगे।
- दाल को जल्दी पकाने के लिए उसमें थोड़ा-सा घी, चुटकी भर हल्दी व हींग और जरा-सा नमक व चीनी डालिए, इससे दाल आसानी से पकेगी और उसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी।
- पूरियां नरम व फूली हुई बनें इसके लिए आटा गूंथते समय पानी के बदले दूध का उपयोग करें।

सब्जियां पकाने के दौरान जब तक सब्जी गले नहीं तब तक उसमें नमक न डालें। सब्जियों में जल्दी नमक डालने से उनकी न्यूट्रीशनल वैल्यू कम हो जाती है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

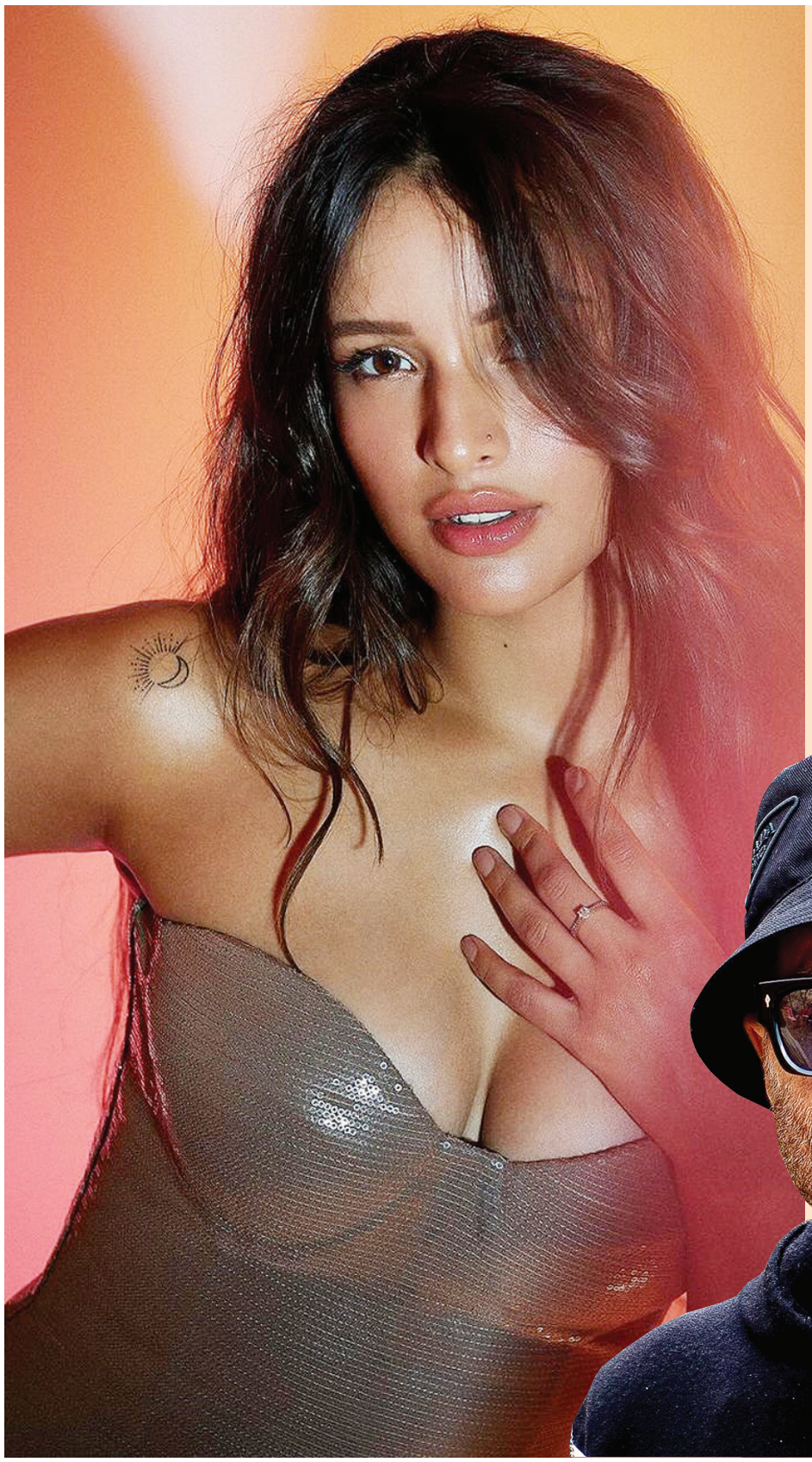

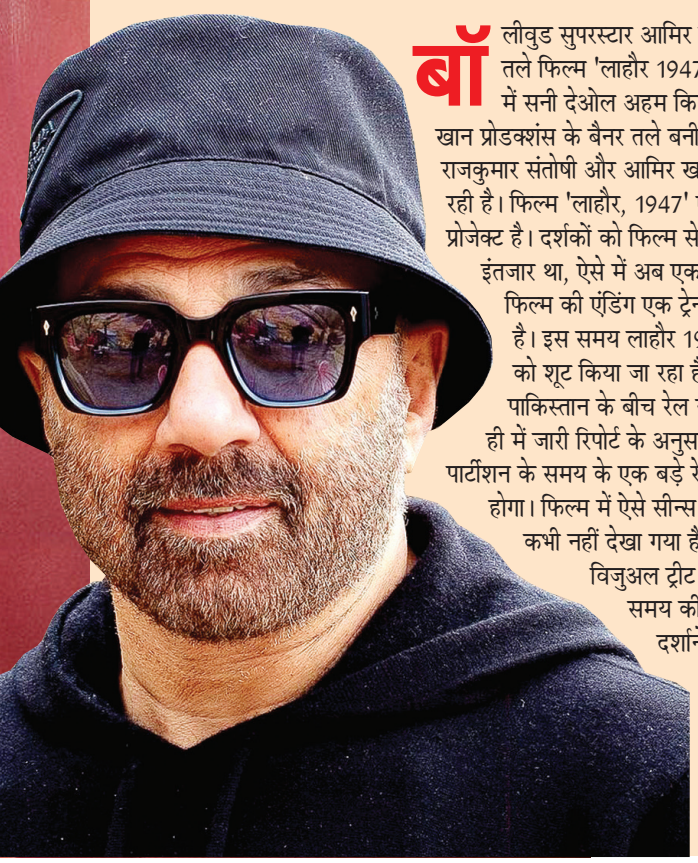

सिल्वर स्क्रीन पर परवीन बॉबी का किरदार निभायेंगी तृप्ति डिमरी

बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी सिल्वर स्क्रीन पर परवीन बॉबी का किरदार निभाती नजर आ सकती है। तृप्ति डिमरी फिल्म 'एनिमल' के बाद बैड न्यूज' में नजर आई हैं। चर्चा है कि तृप्ति डिमरी, परवीन बॉबी की बायोपिक में नजर आ सकती हैं। परवीन बॉबी की बायोपिक को लेकर भी लंबे वक्त से चर्चा है। यह फिल्म लेखिका करिश्मा उपाध्याय द्वारा लिखित उनकी जीवनी, 'परवीन बाबीः ए लाइफ' पर आधारित होगी। इस फिल्म में तृप्ति, परवीन बॉबी की भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं। पहले इस किरदार को अदा करने को लेकर उर्वशी रौतेला का नाम सामने आ रहा था। लेकिन, अब तृप्ति के नाम की चर्चा है। तृप्ति डिमरी की आने वाली फिल्मों में कार्तिक आर्यन के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' और राजकुमार राव के साथ 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' शामिल है।

सनी देओल की लाहौर 1947 का क्लाईमैक्स सीन होगा धमाकेदार

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म 'लाहौर 1947' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में सनी देओल अहम किरदार में नजर आएंगे। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ये फिल्म सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान को पहली बार एक साथ ला रही है। फिल्म 'लाहौर, 1947' एक बहुत ही इंतज़ार वाली मेगा प्रोजेक्ट है। दर्शकों को फिल्म से जुड़ी अपडेट का बेसब्री से इंतजार था, ऐसे में अब एक रोमांचक खबर आई है कि फिल्म की एंडिंग एक ट्रेन सीक्वेंस के साथ होने वाली है। इस समय लाहौर 1947 के लिए एक अहम सीन को शूट किया जा रहा है। इस सीन में भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यात्रा को दिखाया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर 1947 की शूटिंग पार्टीशन के समय के एक बड़े रेल सीक्वेंस के साथ खत्म होगा। फिल्म में ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विजुअल ट्रीट होने वाला है, जिसे पार्टीशन के समय की उथलपुथल और भावनाओं को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है। इस सीक्वेंस की शूटिंग कई हफ्तों तक बड़े कास्ट और क्रू के साथ होने वाली है, ताकि दर्शकों को नया अनुभव का एहसास कराया जा सके।

नागा चैतन्य ने की शोभिता धुलिपाला संग सगाई

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य ने आखिरकार शोभिता धुलिपाला से सगाई कर ली है। नागा चैतन्य सामंथा रुथ प्रभु से अलग होने के बाद से ही शोभिता धुलिपाला को डेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं बोला था। नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने 8 अगस्त को सगाई की। नागार्जुन ने सगाई की तस्वीरें शेयर करके बेटे-बहू को शुभकामनाएं दी है। नागार्जुन ने शोभिता का परिवार में स्वागत किया है। तस्वीरों में शोभिता पीच कलर की साड़ी पहने दिख रही हैं। वहीं नागा चैतन्य व्हाइट कलर के कुर्ता-पायजामा पहने दिख रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए नागार्जुन ने लिखा, हमें अपने बेटे नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से सगाई की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो आज सुबह 9:42 बजे हुई!! हमें अपने परिवार में उनका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। खुशहाल कपल को बधाई! उनके जीवन भर प्यार और खुशियों की कामना करता हूं। भगवान भला करे! 8.8.8 अनंत प्रेम की शुरुआत। बता दें कि नागा चैतन्य की पहली शादी साल 2017 में सामंथा रुथ प्रभु से हुई थी। दोनों ने शादी के चार साल बाद अक्टूबर 2021 में अलग होने की घोषणा की थी। इसके बाद से नागार्जुन का नाम शोभिता धुलिपाला से जुड़ रहा था।